155वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 16/10/2014 के कार्यवृत

155वी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 16/10/2014 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के आंचलिक कार्यालय भोपाल के सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई.

प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य अतिथि, ने बैठक में शासन द्वारा प्रयोजित सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की व सफल कार्यान्वयन हेतु सुझाव दिये. बैठक श्री ॲन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव मध्य पद्रेश शासन व श्री आर. के. गोयल, कार्यपालक निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की सहअध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक में उपस्थित अन्य सम्मानीय अधिकारियों की सूची संलग्न है.

सदन में उपस्थित सभी गणमान्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये श्री उमेश कुमार सिंह संयोजक एवं फील्ड जनरल मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने बैठक की शुरुआत की. अपने स्वागत भाषण में उनके द्वारा देश-प्रदेश एवं बैंकों से जुडे पहलुओं पर प्रकाश डालते हुये सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में कुछ महिनों से नई ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है एवं प्रधान मंत्री जन धन योजना, स्वच्छता अभियान, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समीट 2014, "मेक इन इण्डिया" इत्यादी के माध्यम से नव चेतना की जाग्रति हुई है. उनके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का बैठक में पधारकर अपने आशीरवचनों से मार्ग दर्शन देने के लिये आभार व्यक्त किया. तत्पश्चात पुष्प गुच्छ से श्री आर.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक,सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया.

श्री गोयल द्वारा अपने उद्बोधन में देश, प्रदेश एवं बैंको के आर्थिक परिदृश्य का विवरण प्रस्तुत किया जो कि निम्नानुसार है:

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 155वीं बैठक में राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो आज विकास के पर्याय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता के प्रतीक बन चुके हैं का, अपने बैंक की ओर से तथा व्यक्तिगत रूप से हार्दिक अभिवादन, स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं ।

- मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की यह 155वीं बैठक जो इस वित्तीय वर्ष की दूसरी बैठक है , कई मामलों मे ऐतिहासिक होने जा रही है क्यों कि यह बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हो रही है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन कराया गया जिससे न केवल मध्य प्रदेश राज्य को एक नई पहचान मिली है बल्कि राज्य के विकास को एक नई दिशा देने में मील का पत्थर साबित होगी ।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 2012-13 में (4.5 प्रतिशत) थी जो 2013-14 में (4.7 प्रतिशत) हो गई जिसका मुख्य कारण कृषि में विकास दर का बढ़ना रहा।
- उत्पादन में बढ़ोत्तरी, भुगतान संतुलन की संतोष जनक स्थिति तथा वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधारों के कारण वर्ष 2014-15 में विकास दर 5.4 प्रतिशत से 5.9 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।
- वर्ष 2013-14 में राज्य ने 11.08 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त कर देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय औसत मात्र 4.74 प्रतिशत रहा है।
- राज्य में कृषि की विकास दर 24 प्रतिशत रही जिसका मुख्य कारण सिंचाई परियोजनाओं पर जोर देना तथा पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धि रही ।
- औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर जोर देने तथा उद्यमियों का एक समूह बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रू. 6.79 लाख करोड़ (लगभग 100 बिलियन डालर) के प्रस्ताव आगामी कुछ वर्षों में पूरे किए जाएंगे।
- समिट के दौरान पूरा एक दिन केवल एमएसएमई क्षेत्र के लिए समर्पित किया गया।
- राज्य सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति 2014 की घोषणा की है जिसमें निवेशको को पर्यावरण सुधार की जगह होगी।
- मैं समझता हूं कि सरकार ने विभिन्न रोजगारमूलक योजनाओं को मात्र तीन योजना में समाहित करने से एमएसई क्षेत्र में बैंको द्वारा और गहन प्रयास करने के अवसर उपलब्ध कराये है।

- प्रधानमंत्री जन धन योजना में बैंक बढ़ चढ़ कर सहभागिता कर रहे हैं और योजना को सफल करने में अपेक्षित सहयोग दिया जा रहा है।
- योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 36 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
- 11 अक्टूबर 2014 तक उप सेवा क्षेत्रों का 80 प्रतिशत भाग शाखाओं एवं बैंक मित्रों द्वारा देखा जा चुका है।
- इसी तिथि तक उप सेवा क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक सर्वे एवं वार्डों में 36 प्रतिशत सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है।
- मैं यह आशा करता हूं कि आज की चर्चा काफी सार्थक होगी तथा बैंक वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही मैं यह उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार विकास और वसूली का उचित वातावरण बनाने मे आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी ।

  मैं अपने सभी बैंकर्स साथियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपना सर्वोतम योगदान देने में तत्पर रहेंगे।

इस बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आशा करता हूं कि राज्य में बैंकों के क्रियाकलापों के सफल निष्पादन हेतु आप सभी गम्भीर चर्चा करेंगे तथा अपने बहुमूल्य सुझाव/ विचार प्रस्तुत करेंगे ताकि राज्य के समग्र विकास में योगदान दिया जा सके।

अंत में एक बार पुन: मैं माननीय मुख्यमंत्री का बैठक में उपस्थित होने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं.

श्री गोयल द्वारा प्रस्तुति के पश्चात माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश ने बैंक एवं शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया. अपने विचार प्रस्तुत करते हुये उन्होंने कहा कि वे आशावान हैं एवं आत्म विश्वास से भरे हुये हैं कि बैठक की चर्चा सार्थक होगी व इससे प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर होगा. मध्य प्रदेश एक बीमारु राज्य कहलाता था जो कि विकास दर की दृष्टि से देखने पर आज देश का अग्रिम प्रदेश बन गया है. लगातार चार वर्ष से मध्य प्रदेश की विकास दर 9 प्रतशित से ज्यादा रही है. केवल कृषि की विकास दर को देखें तो, यह 20 से 24 प्रतिशत पिछले दो वर्षो में रही है जो कि विश्व में सर्वाधित है. देश का 40 प्रतिशत जैविक उत्पाद मध्य प्रदेश में हो रहा है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आगे कहा कि वे चाहते हैं कि समृद्धि के लिये प्रदेश केवल कृषि पर ही निर्भर न रहे अपितु औघोगिक विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है. इससे युवा वर्ग के लिये रोजगार की संभावना को बढावा मिलेगा और प्रति व्यक्ति आय में बढोत्तरी एवं जीवन स्तर में सुधार होगा. संसाधन के क्षेत्र में कार्य करना भी उतना ही आवश्यक है. प्रदेश को पावर सरप्लस बनाना मुख्य मंत्री जी ने अपना एक सपना व लक्ष्य बताया.

उनके द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समीट का जिक्र किया गया जो कि 8, 9 एवं 10 सितम्बर 2014 को इन्दौर में सम्पन्न हुई. सदन को बताया कि 32 देशों से प्रतिनिधि व देश का सम्पूर्ण उद्योगिक समूह सम्मेलन में उपस्थित थे व निवेश की दृष्टि से प्रदेश की सम्भावनाओं को पंख लगा दिये. रुपये 6,79,000 करोड के निवेश की संभावनाए हुई हैं जिससे मध्य प्रदेश की “ब्रांडिंग” में बढोत्तरी आयी है. उनके द्वारा मध्य प्रदेश को देश का अग्रिम प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखकर कार्य करने का आव्हान किया गया एवं बैंको को उदारता पूर्वक व सकारात्मक दृष्टिकोण से सूक्ष्म और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने का आग्रह किया गया. प्रदेश के युवा बच्चों एवं कारीगरों को उचित समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर बैंक “मेक इन मध्य प्रदेश” को सफल बनायें. उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि स्वरोजगार योजनाओं के लिये पात्र हितग्राहियों का चयन कर निर्धारित समय सीमा में बैंकों को प्रकरण प्रायोजित किये जायें. प्रदेश में वेंचर केपीटल फंड बनाया जा रहा है. इसमें मध्य प्रदेश शासन भी इक्विटी प्रदान करेगी. युवा प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार हैं. बैंकें अपने सहयोग से इसमें प्राण फूंके एवं आगे आकर इनका जीवन स्तर ऊपर उठाने हेतु स्वरोजगार योजनाओं को सफल बनायें.

माननीय मुख्य मंत्री जी के उद्‌बोधन के पश्चात कार्यसूची (ऐजेण्डा) के बिन्दुओं पर चर्चा हुई व शासन द्‌वारा प्रयोजित योजनाओं की समीक्षा की गयी. कार्यसूची अनुसार लिये गये निर्णय एवं होने वाली अग्रिम कार्यवाही निम्नवत हैं:

	कार्यसूची विषय	निर्णय	अग्रिम कार्यवाही - अपेक्षित ऐजेंसी
1	प्रधानमंत्री जन-धन योजना	- अभी भी लगभग 2393 एस.एस.ए. में बी.सी.ए. नहीं लगाए गये हैं, जिसमे कि बड़ा भाग मध्यांचल ग्रामीण बैंक/भारतीय स्टेट बैंक एवं इलाहाबाद बैंक का है. इन बैंकों द्‌वारा आश्वासन दिया गया कि 31.10.2014 तक सभी एस.एस.ए. में बी.सी.ए. नियुक्त कर दिये जाएंगे. बी.सी.ए. द्‌वारा एस.एस.ए. का सर्वे कार्य जिसमें कि एस.एस.ए. के कुल परिवारों में से कितने परिवार के खाते खोलने बाकी है का आंकलन करने का कार्य सभी बैंकों द्‌वारा 31/10/2014 तक पूर्न हो जाना चाहिये. - सभी ऐसे चिन्हित परिवारों के खाते, 31/12/2014 तक खुल जाने चाहिये. - दूरसंचार विभाग के अनुसार जिन 49000 गांव में, कनेक्टीविटी वॉयस कवरेज की है, वहां डेटा कनेक्टीविटी का वेरीफिकेशन किया जाये जहां कनेक्टिीविटी की समस्या है दूरसंचार वि भाग द्‌वारा कहा गया है कि वहां बैंकों द्‌वारा वी-सेट का उपयोग किया जावे. - जहां तक हो सके समग्र आई-डी को खाते में जोडा जाये एवं समग्र न. को रुपये कार्ड पर प्रिंट किया जाए.	- बैंक - बैंक - बैंक/राज्य शासन. -बैंक/सामाजिक न्याय विभाग.
2	वार्षिक साख योजना	- साख योजना को गति प्रदान करने हेतु बैंक कार्ययोजना बनाये एवं उस पर अमल करें.	- बैंक

	2014-15	- कृषि क्षेत्र में स्केल ऑफ फायनेंस में बढोत्तरी करने हेतु 51 में से 20 जिलों की डी.एल.टी.एफ. करना बाकी है, वहां डी.एल.टी.एफ. की बैठक शीघ्र की जायें. - किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित सभी किसानों की सूची राज्य शासन द्वारा बैंकों को प्रदान की जाये. -आयुक्त, संस्थागत वित्त, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, एक बैठक कर एस.एस.ए. के अनुसार के.सी.सी. से वंचित किसानों की सूची बैंकों को उपलब्ध करा दी जाये. -राज्य शासन द्वारा सभी छोटे व बटाई पर कार्य करने वाले किसानों को "कल्टीवेटर लायसेंस" जारी करने की प्रक्रिया को बनाने में तेजी लाएं ताकि उनको भी "केसीसी" से जोड़ा जा सके. सहकारिता विभाग/सहकारी बैंकों द्वारा चिन्हित पात्र किसानों(लगभग 15 लाख) को सभी बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से दी.31.03.2015 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाना सुनिश्चित किया जाय - उद्योग क्षेत्र के लक्ष्यों को बढाया जाये.	- नाबार्ड/जिला प्रशासन/एलडीएम - राज्य शासन - राजस्व विभाग - राज्य शासन / बैंक
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीए मईजीपी)	- तीनों ऐजेन्सीयों (DIC, KVIC, KVIB) द्वारा बैंकों को समयवधि (31/12/2014) में प्रकरण भेजे जायें, एवं प्रकरणों की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाये. जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिती की बैठक सुनिश्चित करते हुए लक्ष्यानुसार प्रकरण प्रायोजित किये जायें. - के.वी.आई.सी. द्वारा योजना की समीक्षा हर महिने की जाये.	- डी.आई.सी./ के.वी.आई.सी./ के.वी.आई.बी. - के.वी.आई.सी.

4	मुख्य मंत्री युवा उद्यमी एवं स्वरोजगार योजना	- मु.मं. उद्यमी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले से 25-50 प्रकरण प्रायोजित किये जायें तथा प्रत्येक प्रकरण की राशि उद्योग स्थापित करने हेतु पर्याप्त हो. माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा एम.एस.ई. क्षेत्र के लक्ष्यों को पुनरीक्षित करने की अपेक्षा की गयी. राज्य शासन की समस्त योजनाओं अंतर्गत दि. 31.12.2014 तक लक्ष्यानुसार प्रकरण प्रायोजित करने तथा दि.31.03.2015 तक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रकरणों की स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया. - योजना की पाक्षिक समीक्षा की जाये.	- उद्योग विभाग. /बैंक - उद्योग विभाग/बैंक
5	मु.मं.ग्रा.आवास मिशन.	- प्रकरणों में दूसरी किश्त जारी करने की अवधि को बैंके न बढायें. - औपचारिकताऐं पूरी करने में विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाये. - कुछ बैंकों की शाखाओं को इस योजना के निर्देश नहीं पहुंचे हैं, जो कि तुरंत जारी करें एवं अपनी वेवसाईड पर भी अपलोड करें. - विभाग द्वारा आंशिक रुप से वितरित प्रकरणों की सूची बैंकों को उपलब्ध करा दी जाये. महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को सूचित किया गया कि योजना अंतर्गत सभी शाखाओं कोलक्ष्य अनुरूप प्रकरणों की स्वीकृति एवं वितरण के निर्देश जारी किये जा चुके हैं -विभाग द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बैंकों के साथ भी एम.ओ.यू. निष्पादित किये जायें जिससे कि बैंक शाखाओं का उपयोग हो सके.	- बैंक / विभाग

6	उच्च शिक्षा ऋण	- उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में आवेदकों की संख्या सुधारने हेतु एक कमेटी का गठन किया जावे एवं कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों को शीघ्रता से अमल में लाया जावे. - हेलम्स पोर्टल को बडे शैक्षणिक संस्थानों से जोडने का प्रयास जारी है ताकि अधिकाधिक आवेदक हेलम्स के जरिये ही आवेदन करें ताकि कुल आवेदकों की संख्या ज्ञात हो सके. - शिक्षा ऋण के क्षेत्र में बढते हुये एन.पी.ए. को रोकने हेतु बैंक व शासन आपस में सहयोग कर सार्थक प्रयास करें. - प्रायवेट बैंक शिक्षा ऋण में अपनी भागीदारी बढाकर अपना दायित्व बढायें.	- डी.आई.एफ./बैंके - डी.आई.एफ. - बैंक / राज्य प्रशासन - प्रायवेट बैंकें
7	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एन.आर.एल. एम.)	- स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोडने का कार्य मिशन मोड में किया जाये. - स्व-सहायता समूहों का सम्मेलन बुलाया जाये. - स्व-सहायता समूहों की सफलता की कहानियों को विभाग द्वारा प्रचारित किया जाये.	- राज्य शासन
8	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	- प्रकरणों के निपटान हेतु बैंकों में शुक्रवार का दिन, समय दोपहर 3 बजे से सांय 5 बजे तक निर्धारित किया गया. अन्य कठिनाईयों के समाधान हेतु पृथक से विभाग स्तर पर बैंकों के साथ एक बैठक की जाय.	- नगरीय प्रशासन/बैंक
9	अग्रिम जमा अनुपात	- सभी ऐसे जिलों में जहां साख जमा अनुपात 40 प्रतशित से कम है में विशेष अभियान चला कर रहवासियों को बैंकों से जोडा जाये. - साख जमा अनुपात उपसमिति की बैठक में जिले के एल.डी.एम. व कलेक्टर को भी आमंत्रित किया जावे.	- डी.आई.एफ./बैंक

10	वीवर्स क्रेडिट कार्ड	- सभी पात्र बुनकरों के क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु आवेदन पत्र बैंकों को प्रायोजित किये जायें. इस हेतु विभाग द्वारा विशेष मुहीम चलायी जाय. विभाग द्वारा " केस-स्टडी" भी करायी जाये.	- राज्य शासन
11	राजीव ऋण योजना	- योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक बुलाकर जल्द से जल्द उचित निर्णय लिये जायें.	- राज्य शासन/ बैंक
12	आरसेटी	- एल.डी.एम. के ऑफिस को आरसेटी भवन में रखने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गयी कि प्रशिक्षण के कार्य में आने वाले किसी भी कक्ष को अग्र.बै.अ. कार्यालय हेतु उपयोग में नहीं लाया जाएगा. इस हेतु अग्र.बै.अ. को अलग रिक्त कक्ष देना उचित होगा. सदन ने यह माना कि अग्र.बै.अ. कार्यालय को आरसेटी की प्रशासनिक क्षमता एवं स्वयं आरसेटी के संचालन में बेहतरी होगी.	- पंचायत विभाग / बैंक/समस्त अग्रणी बैंक
13	प्राथमिक क्षेत्र ऋणों पर स्टॉम्प ड्यटी	- प्रा.क्षे. के ऋणों के संबंध में लिये जाने वाले अनुबंध पत्र पर स्टॉम्प ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष विचारधीन है.	- वाणिज्यिक कर विभाग.
14	एस.एल.बी.सी. की उप सिमतियों के सुझावों को स्वीकार किया जाना	- सभी उपसमितियों में लिये गये सुझावों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया.	- उपसमितियों के कार्यवृत के अनुसार.

कार्यसूची के अनुसार बिन्दुओं पर चर्चा के पश्चात नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डा. राजेन्द्र कुलकर्णी द्वारा सदन को बताया गया कि कृषि क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा अभी केपीटल ऐसेट के निर्माण में बैंकों का योगदान बढाना आवश्यक हो गया है. इस संबंध में उनके द्वारा जारी पुस्तक "MODEL SCHEME ON AGRICULTURE AND ALLIED

ACTIVITIES VOLUME - 1" का विमोचन माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों द्वारा किया गया. ततपश्चात बैंक ऑफ बडौदा के महाप्रबंधक श्रीनागेश श्रीवास्तव द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उपस्थिति गणमान्य अधिकारियों को बैठक में आकर अपने सुझाव देने पर आभार व्यक्त किया. सेन्ट्रल बैंक के कार्यपालक निदेशक द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी व बैठक में उपस्थित अधिकारियों को बैठक सफल बनाने हेतु धन्यवाद दिया गया.

बैठक में उपस्थित गणमान्य सदस्यों की सूची

- **श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश**
- **श्री एन्टोनी डी सा, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन (अध्यक्ष)**
- **श्री आर. के. गोयल, कार्यपालक निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.(सह अध्यक्ष)**
- **श्रीमती अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास म.प्र.शासन.**
- **श्री राकेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव, कुटीर एवं ग्रामोघोग, म.प्र.शासन.**
- **श्री अजय नाथ, अपर मुख्य सचिव वित्त, म.प्र.शासन.**
- **श्री के.के.सिंह, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन.**
- **श्री जे.एन. कन्सोटिया, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, म.प्र.शासन.**
- **श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव, सहकारिता, म.प्र.शासन.**
- **श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण, म.प्र.शासन.**
- **श्रीमती अल्का उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ग्रा.स.आ.मिशन.**
- **श्री विवेक अग्रवाल, आयुक्त, संस्थागत वित्त, म.प्र. शासन.**
- **श्रीमती सुधा चौधरी, प्रबंध निदेशक, म.प्र.खादी बोर्ड.**
- **श्री व्ही. एल. कान्थाराव, आयुक्त, उद्योग एवं श्रम, म.प्र.शासन.**
- **श्री संजय शुक्ला आयुक्त, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग, म.प्र.शासन.**
- **श्री जे.एन. मालपानी, आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास.**
- **श्री अनुपम राजन, सचिव, उद्योग, म.प्र.शासन.**
- **श्री एस.एन. शुक्ला, राज्य निदेशक, के.वी.आई.सी.**
- **श्री एच.बी. सिंह, सहायक निदेशक, पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग.**
- **श्री डॉ. मन्डले, निदेशक एम.एस.एम.ई.**
- **श्री एल.एम. बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.एल.एम. म.प्र.शासन.**
- **श्री सतीश गुप्ता, संयुक्त संचालक, संस्थागत वित्त**
- **श्री ए.एस. परमार, संयुक्त संचालक, कृषि**
- **श्री ए.के. जैन, संयुक्त संचालक, शिक्षा**
- **श्री पंकज पोरवाल, निदेशक, दूरसंचार विभाग**
- **श्री विनोद गुप्ता, डीडीजी (TERM),डी.ओ.टी.**
- **श्री मुरली राधाकृष्णन, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, म.प्र.**
- **श्री राजेन्द्र कुलकर्णी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड.**
- **श्री आर. के. गोयल, कार्यपालक निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.**
- **श्री उमेश कु. सिंह, संयोजक एवं फील्ड जनरल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

एवं

रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक एवं म.प्र. शासन के अन्य गणमान्य अधिकारी.